# MAIN NEWS HEADLINE  केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर  दिल्ली में श

## विषय सूची (Table of Contents):

>> 8वें वेतन आयोग की दिल्ली में मैराथन बैठकें शुरू  जानें मुख्य अपडेट...
>> बैठक की समय-सीमा और मुख्य उद्देश्य...
>> कर्मचारी यूनियनों की सक्रिय भागीदारी...
>> जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किन अहम मुद्दों पर हो रही है चर्चा?...
>> तीन सदस्यीय पैनल की संरचना...
>> चर्चा के प्रमुख बिंदु...
>> कर्मचारियों की बड़ी मांग  फिटमेंट फैक्टर 3.83 और न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 रुपय...
>> NC-JCM की सिफारिशें और 3.83 फिटमेंट फैक्टर...
>> न्यूनतम बेसिक सैलरी में संभावित उछाल...
>> पेंशनर्स के लिए खास  फुल पेंशन, फैमिली पेंशन और मेडिकल भत्ते में भारी बढ़ोतरी की...
>> लास्ट ड्रॉन सैलरी का 67  पेंशन करने की मांग...
>> बुजुर्ग पेंशनभोगियों और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस पर अपडेट...
>> भत्तों पर अपडेट  मकान किराया भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव और महंगाई भत्ते का मूल...
>> X, Y और Z श्रेणी के शहरों के लिए HRA संशोधन...
>> महंगाई भत्ता (DA) का बेसिक सैलरी में विलय...
>> 8वां वेतन आयोग सरकार को कब सौंपेगा अपनी फाइनल रिपोर्ट? जानें संभावित समय-सीमा...
>> 18 महीने का कार्यकाल और मई-जून 2027 की समय-सीमा...
>> दिल्ली के बाद इन प्रमुख शहरों का दौरा करेगा वेतन आयोग...
>> चेन्नई, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और जयपुर में क्षेत्रीय परामर्श...
>> निष्कर्ष...
>>  महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर...

8th Pay Commission Latest Update:केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग ने 7 अगस्त से नई दिल्ली में कर्मचारी संगठनों और पेंशन यूनियनों के साथ उच्च स्तरीय मैराथन बैठकें शुरू कर दी हैं। यह दौर 10 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें लाखों सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर और भत्तों से जुड़े अहम मुद्दों पर सीधे संवाद किया जा रहा है।

यदि आप भी केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं और अपने वेतन संशोधन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो यह लेटेस्ट अपडेट 2026 आपके लिए बेहद खास है। सरकार द्वारा तय की गई 18 महीने की समय सीमा के भीतर आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। आइए जानते हैं दिल्ली में चल रही इन बैठकों के मुख्य बिंदु और कर्मचारियों द्वारा रखी गई

प्रमुख मांगें।

इसके अलावा, विभिन्न सरकारी लाभों और नियमों में बदलाव की जानकारी के लिए आप1 जनवरी से बदलेंगे नियम! 8वें वेतन आयोग से सैलरी में बंपर इजाफापर भी पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं।

## 8वें वेतन आयोग की दिल्ली में मैराथन बैठकें शुरू: जानें मुख्य

नई दिल्ली में आयोजित हो रही यह 4 दिवसीय मैराथन बैठक आयोग के कार्यकाल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। 7 अगस्त से शुरू हुई यह बातचीत 10 अगस्त तक चलेगी, जिसमें देश भर के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं।

## बैठक की समय-सीमा और मुख्य उद्देश्य

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने की समयावधि दी थी। आयोग पहले ही अपने कार्यकाल का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर चुका है, इसलिए दिल्ली की यह बैठक अंतिम सिफारिशें तैयार करने की दिशा में मील का पत्थर मानी जा रही है।

## कर्मचारी यूनियनों की सक्रिय भागीदारी

नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) समेत प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन इस बैठक में शामिल होकर कर्मचारियों का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं। आधिकारिक अधिसूचना की पूरी PDF लिस्ट और सिफारिशों के ड्राफ्ट पर भी चर्चा जारी है।

## जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किन अहम मुद्दों प

8वां वेतन आयोग एक 3-सदस्यीय निकाय है जिसका औपचारिक गठन 3 नवंबर, 2025 को किया गया था। इस आयोग का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं।

## तीन सदस्यीय पैनल की संरचना

इस पैनल में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (अध्यक्ष) के साथ प्रोफेसर पुलक घोष (सदस्य) और पंकज जैन (सदस्य-सचिव) शामिल हैं। यह टीम सभी हितधारकों की मांगों का गहराई से अध्ययन कर रही है।

## चर्चा के प्रमुख बिंदु

>> फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor):न्यूनतम और अधिकतम बेसिक सैलरी तय करने का मुख्य आधार।

>> बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी:मौजूदा 18,000 रुपये के न्यूनतम वेतन में बड़ा संशोधन।

>> भत्तों का पुनर्गठन:HRA, TA और अन्य मेडिकल अलाउंस का नए सिरे से निर्धारण।

>> पेंशन सुधार:सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा मजबूत करना।

देश भर में चल रहे अन्य कल्याणकारी अभियानों और योजनाओं की जानकारी के लिएपीएम किसान, आयुष्मान और आवास योजना का लाभ? 17-18 जून खासलेख भी देखें।

## कर्मचारियों की बड़ी मांग: फिटमेंट फैक्टर 3.83 और न्यूनतम बेस

कर्मचारी यूनियनों की सबसे प्रमुख मांग फिटमेंट फैक्टर में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को लेकर है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 3.83 करने की पुरजोर मांग की जा रही है।

## NC-JCM की सिफारिशें और 3.83 फिटमेंट फैक्टर

यदि आयोग 3.83 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में अब तक का सबसे बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। इससे कर्मचारियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार आएगा।

## न्यूनतम बेसिक सैलरी में संभावित उछाल

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह है। यदि 3.83 का गुणांक लागू होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी सीधे बढ़कर 69,000 रुपये प्रति माह हो जाएगी। हालांकि, इस प्रस्ताव पर आयोग अंतिम फैसला सभी आर्थिक पहलुओं की समीक्षा के बाद ही लेगा।

## पेंशनर्स के लिए खास: फुल पेंशन, फैमिली पेंशन और मेडिकल भत्ते

दिल्ली में जारी मैराथन बैठकों में पेंशनभोगियों के अधिकारों और उनकी मांगों पर भी विस्तृत चर्चा हो रही है। पेंशनर यूनियनों ने

बुजुर्गों के स्वास्थ्य और जीवन यापन के खर्च को देखते हुए कई ठोस प्रस्ताव रखे हैं।

## लास्ट ड्रॉन सैलरी का 67% पेंशन करने की मांग

पेंशन यूनियनों ने मांग की है कि पूर्ण पेंशन (Full Pension) की राशि को कर्मचारी द्वारा रिटायरमेंट के समय प्राप्त अंतिम आहरित वेतन (Last Drawn Salary) का कम से कम 67% तय किया जाए। इसके साथ ही फैमिली पेंशन को भी 50% तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।

## बुजुर्ग पेंशनभोगियों और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस पर अपडेट

>> अतिरिक्त पेंशन:65 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई दरों से अतिरिक्त पेंशन दी जाए।

>> मेडिकल अलाउंस (FMA):नॉन-CGHS क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनर्स के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव।

## भत्तों पर अपडेट: मकान किराया भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव और

कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में भत्ते (Allowances) एक अहम भूमिका निभाते हैं। बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए HRA और DA के ढांचे में बड़े बदलावों की सिफारिश की गई है।

## X, Y और Z श्रेणी के शहरों के लिए HRA संशोधन

यूनियनों ने शहरों की वर्गीकरण श्रेणी के अनुसार हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में निम्नलिखित संशोधनों की मांग की है:

>> X श्रेणी (मेट्रो शहर):HRA बढ़ाकर 36% किया जाए।

>> Y श्रेणी (बड़े शहर):HRA बढ़ाकर 24% किया जाए।

>> Z श्रेणी (छोटे शहर ग्रामीण):HRA बदलकर 12% किया जाए।

## महंगाई भत्ता (DA) का बेसिक सैलरी में विलय

वर्ष 2026 की शुरुआत तक महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 50% का आंकड़ा पार करने का अनुमान है। नियमानुसार, जब DA 50% से अधिक हो जाता है, तो यूनियनों की मांग है कि इसे मूल वेतन (Basic Pay) में मर्ज कर दिया जाए और शून्य से नए सिरे से महंगाई भत्ते की गणना शुरू की जाए।

अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की अन्य प्रमुख खबरों का विश्लेषण जानने के लिए पढ़ेंMAIN NEWS HEADLINE: भारत अपना रुख साफ करे , शेख हसीना ऐसा क् या करने।

## 8वां वेतन आयोग सरकार को कब सौंपेगा अपनी फाइनल रिपोर्ट? जानें

सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट कब सबमिट करेगा और नए वेतनमान कब से प्रभावी होंगे।

## 18 महीने का कार्यकाल और मई-जून 2027 की समय-सीमा

3 नवंबर, 2025 को गठित 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल 18 महीने का तय किया गया है। इस समय सीमा के अनुसार आयोग मई या जून 2027 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप सकता है। रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद इसे लागू करने की समय-सीमा और तिथि की घोषणा की जाएगी।

## दिल्ली के बाद इन प्रमुख शहरों का दौरा करेगा वेतन आयोग

नई दिल्ली में हितधारकों और कर्मचारी संगठनों के साथ 10 अगस्त तक चलने वाली मैराथन बैठकों को पूरा करने के बाद 8वां वेतन आयोग जमीनी स्तर पर सुझाव लेने के लिए देश के अन्य हिस्सों का रुख करेगा।

## चेन्नई, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और जयपुर में क्षेत्रीय परामर्श

आने वाले हफ्तों में आयोग की टीम चेन्नई, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और जयपुर जैसे प्रमुख शहरों का दौरा करेगी। वहां स्थानीय कर्मचारी यूनियनों, राज्य स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों और पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ बैठकें करके क्षेत्रीय समस्याओं और मांगों की समीक्षा की जाएगी।

## निष्कर्ष

दिल्ली में 7 से 10 अगस्त तक आयोजित 8वें वेतन आयोग की मैराथन बैठकें केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के भविष्य के लिए अत्यंत निर्णायक साबित होने वाली हैं। फिटमेंट फैक्टर 3.83, न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये और पेंशन में 67% तक की बढ़ोतरी जैसी मांगें कर्मचारियों की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर हैं।

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोग का यह प्रयास है कि मई-जून 2027 तक एक संतुलित और सर्वसमावेशी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी जाए। आने वाले दिनों में जब आयोग चेन्नई, जयपुर और चंडीगढ़ का दौरा करेगा, तो वेतन संशोधन की इस प्रक्रिया को और अधिक गति मिलेगी। लेटेस्ट अपडेट्स और पीडीएफ लिस्ट जारी होने पर स्टेटस चेक करना जारी रखें।

## महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर

8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर, 2025 को किया गया था। इस 3-सदस्यीय पैनल की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं।

नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) और यूनियनों ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जिससे न्यूनतम सैलरी में भारी बढ़ोतरी हो सके।

यदि यूनियनों द्वारा प्रस्तावित 3.83 फिटमेंट फैक्टर मंजूर होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 69,000 रुपये प्रति माह हो सकती है।

सरकार द्वारा दी गई 18 महीने की समय-सीमा के अनुसार, आयोग मई-जून 2027 के आसपास अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप सकता है।

नई दिल्ली की बैठकों के बाद 8वां वेतन आयोग आने वाले हफ्तों में चेन्नई, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और जयपुर का दौरा कर क्षेत्रीय हितधारकों से परामर्श करेगा।